भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1279
(11 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

महिलाओं का सशक्तीकरण

1279. श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा निजी कंपनियों के सहयोग से महिला उद्यमियों के सामाजिक-आर्थिक समावेशन के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इलेक्ट्रिक साइकिलों के माध्यम से ग्रामीण उद्यमियों के लिए सतत परिवहन (एसटीआरईई) का ग्रामीण महिलाओं को पर्यावरण अनुकूल परिवहन साधन सुलभ करा कर उन्हें सशक्त बनाने संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क): भारत सरकार ने महिला उद्यमियों के सामाजिक-आर्थिक समावेशन के लिए निजी कंपनियों के साथ मिलकर विभिन्न पहल की हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) वर्ष 2011 में शुरू की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई - एनआरएलएम) को कार्यान्वित कर रहा है, जो वित्त, बुनियादी ढांचे और बाजार के अवसरों तक पहुंच जैसे कारकों पर विचार करते हुए अनुकूल ग्रामीण उद्यमिता वातावरण तैयार करने के लिए प्रयासरत है।

देश में संतुलित विकास के लिए महिला उद्यमियों के सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा वर्ष 2016 में स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की गई थी। सरकार स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएस) जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सरकार उद्यमियों को सर्वोत्तम कार्यों को साझा करने में सहायता देने के लिए महिला क्षमता विकास कार्यक्रम (विंग) जैसे कार्यक्रम प्रदान करती है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के उत्पादों को शामिल करने और विपणन के लिए विभिन्न ऑनलाइन मंचों क्रमशः फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड , अमेज़न, फैशनियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (मीशो) और जियोमार्ट के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन कंपनियों द्वारा स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों को निम्नलिखित सहायता प्रदान की जा रही है:

1. स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को ऑनलाइन मंचों से जोड़ना , खाता प्रबंधन और व्यवसाय वृद्धि के लिए प्रशिक्षण देना।

2. उत्पादों का कैटलॉग बनाना।

3.फोटोग्राफी और विषय वस्तु बनाना।

4. स्वयं सहायता समूह के उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए विशिष्ट स्टोर फ्रंट (विशिष्ट पेज) बनाना।

(ख): विद्युत मंत्रालय के तहत एक संयुक्त उद्यम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) और इसकी सहायक कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) ने ग्रामीण उद्यमियों के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल (स्त्री) के माध्यम से सतत परिवहन कार्यक्रम शुरू करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ साझेदारी की है। यह समझौता ग्रामीण स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उनकी परिवहन जरूरतों को पूरा करने और धनार्जन संबंधी गतिविधियों के लिए उनकी पहुँच बढ़ाने के लिए रियायती दरों पर इलेक्ट्रिक साइकिलों की आपूर्ति के माध्यम से छोटे और पर्यावरण-अनुकूल यातायात के साधन (ग्रीन माइक्रो-मोबिलिटी) को बढ़ावा देता है। यह प्रायोगिक परियोजना बिहार, केरल, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में शुरू की गई है।

***